

प्रेषक,

सुभाष कुमार,  
प्रमुख सचिव,  
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,  
देहरादून।

राजस्व अनुभाग-2

देहरादून: दिनांक: 21 जून, 2009

विषय:- स्वयं सेवा संस्थान ऊषा को उच्च शिक्षण संस्थान की स्थापना किये जाने हेतु ग्राम मियाँवाला तहसील देहरादून, जिला देहरादून में कुल 0.3200 है० भूमि क्रय की अनुमति प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-2069/12ए-250(2005-08)/डी०एल०आर०सी० दिनांक-01.09.2008 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय स्वयं सेवा संस्थान, ऊषा को तहसील एवं जिला देहरादून के ग्राम मियाँवाला में उच्च शिक्षण संस्थान की स्थापना हेतु कुल 0.3200 है० भूमि क्रय की अनुमति उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950) (अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2001) (संशोधन) अधिनियम, 2003 दिनांक 15-1-2004 की धारा-154(4)(3)(क)(III) के अन्तर्गत आपके द्वारा संस्तुत खसरा संख्या-472ख के अनुसार निम्नलिखित प्रतिबन्धों/शर्तों के साथ प्रदान करते हैं:-

- 1- क्रेता धारा-129-ख के अधीन विशेष श्रेणी का भूमिधर बना रहेगा और ऐसा भूमिधर भविष्य में केवल राज्य सरकार या जिले के कलैक्टर, जैसी भी स्थिति हो, की अनुमति से ही भूमि क्रय करने के लिये अर्ह होगा।
- 2- क्रेता बैंक या वित्तीय संस्थाओं से ऋण प्राप्त करने के लिए अपनी भूमि बन्धक या दृष्टि बन्धित कर सकेगा तथा धारा-129 के अन्तर्गत भूमिधरी अधिकारों से प्राप्त होने वाले अन्य लाभों को भी ग्रहण कर सकेगा।
- 3- क्रेता द्वारा क्रय की गयी भूमि का उपयोग दो वर्ष की अवधि के अन्दर, जिसकी गणना भूमि के विक्रय विलेख के पंजीकरण की तिथि से की जायेगी अथवा उसके बाद ऐसी अवधि के अन्दर जिसको राज्य सरकार द्वारा ऐसे कारणों से जिन्हें लिखित रूप में अभिलिखित किया जायेगा, उसी प्रयोजन (बी०एड० कॉलेज की स्थापना) के लिये करेगा जिसके लिये अनुज्ञा प्रदान की गयी है। यदि वह ऐसा नहीं करता अथवा उस भूमि का उपयोग जिसके लिये उसे स्वीकृत किया गया था, उससे भिन्न प्रयोजन के लिये विक्रय, उपहार या अन्यथा भूमि का अन्तरण करता है तो ऐसा अन्तरण उक्त अधिनियम के प्रयोजन हेतु शून्य हो जायेगा और धारा-167 के परिणाम लागू होंगे।

- 4- जिस भूमि का संक्रमण प्रस्तावित है उसके भूस्वामी अनुसूचित जाति/जनजाति के न हों और अनुसूचित जाति/जनजाति के भूमिधर होने की स्थिति में भूमि क्रय से पूर्व सम्बन्धित जिलाधिकारी से नियमानुसार अनुमति प्राप्त की जायेगी।
- 5- जिस भूमि का संक्रमण प्रस्तावित है उसके भूस्वामी असंक्रमणीय अधिकार वाले भूमिधर न हों।
- 6- शासन द्वारा दी गई भूमि क्रय की अनुमति शासनादेश निर्गत होने की तिथि से 180 दिन तक वैध रहेगी।
- 7- संस्था द्वारा प्रस्तावित क्रय की जाने वाली भूमि का उपयोग केवल निर्धारित प्रयोजन यथा शैक्षणिक संस्थान-बी0एड0 कॉलेज की स्थापना हेतु ही किया जायेगा।
- 8- बी0एड0 कॉलेज की स्थापना के परिप्रेक्ष्य में सम्बन्धित इकाई द्वारा एन0सी0टी0ई0/उच्च शिक्षा विभाग उत्तराखण्ड शासन एवं आवास विभाग उत्तराखण्ड शासन आदि के द्वारा समय-समय पर निर्गत किये जाने वाले आदेश/निर्देश का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जायेगा।
- 9- संस्था द्वारा 2500 वर्गमीटर भूमि अथवा एन0ई0सी0टी0 से स्वीकृत बी0एड0 पाठ्यक्रम के अन्तर्गत संचालित प्रक्रिया को दृष्टिगत रखते हुए भूमि का उपयोग किया जायेगा तथा शेष भूमि का प्रयोग शिक्षण कार्यों में ही खेल कूद अथवा छात्रावास इत्यादि पर उपयोग में लाया जायेगा, जिसके आलोक में 3200 वर्गमीटर भूमि क्रय का उपयोग शत प्रतिशत बी0एड0 पाठ्यक्रम हेतु भवन इत्यादि का निर्माण कर उक्त भवन में संचालन हेतु प्रयोग किया जायेगा। यदि उक्त भूमि का उपयोग उनके द्वारा किसी अन्य प्रयोजन हेतु किया जायेगा तो यह स्वीकृति स्वतः निरस्त समझी जायेगी।
- 10- बी0एड0 कॉलेज की स्थापना करते हुए बी0एड0 पाठ्यक्रमों का संचालन किये जाने से पूर्व नियमानुसार सम्बन्धित विभागों से इस सम्बन्ध में संस्तुति/सहमति/अनापत्ति प्राप्त की जायेगी।
- 11- किसी दशा में प्रस्तावित क्रेताओं को प्रस्तावित भूमि के अतिरिक्त अन्य भूमि के उपयोग की अनुमति नहीं होगी एवं सार्वजनिक उपयोग की भूमि या अन्य कोई भूमि पर कब्जा न हो इसके लिए भूमि क्रय के तत्काल बाद उसका सीमांकन कर लिया जाय।
- 12- भूमि का विक्रय अपरिहार्य परिस्थितियों के अतिरिक्त अनुमन्य नहीं होगा एवं ऐसी दशा में विक्रय किये जाने हेतु सकारण शासन का अनुमोदन प्राप्त करना होगा।
- 13- योजना प्रारम्भ करने से पूर्व नियमानुसार सम्बन्धित विभागों/संस्थाओं से विधिक व अन्य अनापत्तियाँ/स्वीकृतियाँ प्राप्त कर ली जायेगी।
- 14- सम्बन्धित आवेदक द्वारा भू-उपयोग करने से पूर्व सक्षम एजेन्सी (विनियमित क्षेत्र/विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण/विकास प्राधिकरण) से नियमानुसार अनापत्ति प्राप्त करनी होगी तभी वह भूमि का उपयोग निर्धारित कार्य हेतु कर सकेंगे।



15- उपरोक्त शर्तों/प्रतिबन्धों का उल्लंघन होने पर अथवा किसी अन्य कारणों से, जिसे शासन उचित समझता हो, प्रश्नगत स्वीकृति निरस्त कर दी जायेगी।

कृपया तदनुसार आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(सुभाष कुमार)  
प्रमुख सचिव।

पृ०प०सं०- 204/समदिनांकित 2009

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- मुख्य राजस्व आयुक्त, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 2- सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
- 3- सचिव आवास विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
- 4- आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
- 5- डा० श्री हरेन्द्र सिंह रावत, अध्यक्ष ऊषा सोसाइटी फार ह्यूमन अफेयर्स एण्ड एडवांसमेन्ट, एस०-1, डी०-6 डिफेंस कॉलोनी देहरादून।
- 6- निदेशक एन०आई०सी०, उत्तराखण्ड सचिवालय।
- 7- प्रभारी मीडिया सेंटर उत्तराखण्ड सचिवालय।
- 8- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

  
(संतोष बडोनी)  
अनु सचिव।